

# रोडवेज का चक्का जाम होने के बाद दिया वेतन, यात्री रहे परेशान, सरकार को घाटा अलग से

बल्लबगढ़ (म.ग.) फ़रवरी माह का वेतन जो तमाम सरकारी कर्मचारियों को पहली मार्च तक मिल जाता है, यहां के करीब 1500 रोडवेज कर्मचारियों को 21 मार्च तक भी नहीं मिला तो सभी कर्मचारी हड्डताल पर चले गये। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रूटों पर चलने वाली करीब 150 बसों का चक्का एकदम जाम हो गया। जाहिर है इससे बस यात्रियों के लिये भारी संकट की स्थिति बन गयी। दुग्ने-तिगुने दामों पर वैकल्पिक साधनों से उन्हें यात्रा करनी पड़ी। इसके अलावा सरकारी परिवहन विभाग को लाखों का जाम हुआ वह अलग से।

चक्का जाम करने से 10-12 दिन पूर्व भी 2 बार रोडवेज कर्मियों ने वेतन देने के लिये डिपो में प्रदर्शन किया था। परन्तु पूरी तरह शिथिल एवं बेपरवाह हो चुके प्रबन्धन पर इसका कोई असर नहीं हुआ तब मजबूरन कर्मचारियों को हड्डताल जैसे हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। यदि प्रबन्धन अपने वैधानिक दायित्व का बहन करते हुए निश्चित

समय पर वेतन अदा कर देता तो क्यों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती और क्यों एक दिन की कमाई का नुकसान परिवहन विभाग को उठाना पड़ता?

लेकिन इतनी समझ न तो सरकार को है और न ही प्रशंसन को। इस तरह का ड्रामा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर साल 2-4 बार इस तरह के ड्रामे, राज्य भर में कहीं न कहीं होते रहते हैं। जो बात प्रबन्धन को स्वतः समझ में नहीं आती वह हड्डताल की भाषा से तुरंत समझ में आ जाती है।

भारी घाटे में चलने वाला रोडवेज ऐसा महकमा है जिसे यदि ठिक से चलाया जाये तो इतना कमा कर दे सकता है कि राज्य की दिरदिता दूर हो जाये। परन्तु महकमे की हर शाख पर बैठें उल्लङ्घन करने पर तुले हैं। इस डिपो की 309 बसों में से आधी से अधिक चलने लायक नहीं हैं। वे चलने लायक हो सकती थीं यदि सही ढंग की वर्कशॉप में पर्याप्त मात्रा में

सही मिस्री आदि होते। मूर्खों की सरकार वर्कशॉप का खर्च बचा कर खुश है लेकिन कंडम हुई जा रही बसों से होने वाले नुकसान को काइ चिन्ना नहीं। पक्के एवं स्थाई ड्राइवर-कंडेक्टर के बदले में ठेकदारी में कच्चे रख कर बचत करने की तो सरकार सोचती है लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार स्टाफ़ से जो नुकसान होता है उसकी कोई चिंता नहीं।

कई-कई माह तक डिपुओं के महाप्रबन्धक व अन्य स्टाफ़ की पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं। ऐसे में डिपो राम भरोसे ही चलते हैं। घाटा हो या नफा कोई पूछने वाला नहीं। छोटी-छोटी खरीदारी से लकर बसों तक की खरीदारी चंडीगढ़ में बैठे मंत्री व अफसरों ने अपनी मट्टी में रखी हैं। मक्सद के बल कमीशन को सीधी बसूली। इसी कमीशन के चक्कर में स्टाफ़ हो न हो पर बर्से थोक में खरीद ली जाती हैं। यूं ही नहीं कमाई वाला यह विभाग भारी घाटे वाला बना दिया गया है।

**चार साल पहले मार दिया गया था 39 भारतीयों को, भारत सरकार अब उनके कंकाल लाएगी, मोदी की सुपरमैन छवि की खातिर झूठ बोलती रही थी अब तक**

(जनज्वार विशेष) इराक में 2014 में मारे गए मजदूरों का सच अगर केंद्र सरकार उसी समय बता देती तो मोदी की वैश्विक नेता बनाने की भाजपाई कोशिश को बढ़ा लग जाता और लोग मान लेते कि उनका नेता बेहद कमज़ोर है। एक बार नहीं सात बार संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार नेदावा किया था कि 39 फ़से भारतीय जिंदा हैं, पर अब बताया कि 4 साल पहले ही कर दिए गए थे दफन।

जून 2014 यानी चार साल पहले इराक के मोसुल में अगवा हुए 39 भारतीयों को आईएसआईएस ने मौत के घाट उत्तर दिया था। यह खबर सामने आने के बाद भी मोदी सरकार दावा करती रही कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं उन्हें जल्द ही देश में वापस लाया जाएगा। आईएसआईएस के कब्जे में फ़से भारतीयों के मारे जाने की खबर कोरी अफवाह है।

संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार ने यह फ़र्जी दावा एक बार नहीं 7 बार किया। पहला बयान 23 जून 2014 को, दूसरा 16, 17 और 24 जुलाई 2014 को, फिर 22 अगस्त 2014, उसके बाद 22 जुलाई 2015 और 16 जुलाई 2017 को दिया। भारत सरकार द्वारा दिए गए ये सभी बयान इस बात के दावेदारी के थे कि सभी 39 श्रमिक जिंदा हैं।

मगर अचानक इस दावे से पलटी मारते हुए हमारी माननीय विदेश मंत्री महोदया सुषमा स्वराज ने खुलासा किया कि इराक के बादेश गांव में चार साल से 39 भारतीयों के शव दफन हैं। आईएसआईएस ने मौत के घाट उत्तर दिया था। यह खबर सामने आने के बाद भी मोदी सरकार उनका सिर्फ़ कंकाल लाएगी, वह भी अगर ले आ पाई तो।

सरकार अपने ही देश के नागरिकों की जिंदगियों को लेकर न सिर्फ़ संवेदनशीलता के स्तर पर गफलत में रखने का गुनाह किया, बल्कि अपनी जनता के साथ एक सरकार द्वारा किया गया फ़रेब भी है। क्या एक जनता के लिए बनी सरकार जनता के साथ ही 420 की तरह पेश आ सकती है।

इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि आईएसआईएस के चंगुल से बचकर निकले हरजीत मसीह ने सभी भारतीय मजदूरों के मारे जाने की पुष्टि पहले ही खबर कर दी थी, मगर सरकार ने उसको झूठांकर करार दे दिया था। न सिर्फ़ द्वाटा करार द्वारा एक बल्कि 6 महीने जेल में रखा। वह पिछले 4 सालों से कहर हाते हैं कि उसके साथ के सभी 39 लोगों को मार दिया गया।

पर सरकार हरजीत मसीह के दावे को इसलिए कान नहीं देती रही क्योंकि इससे मोदी की माहन बनती वैश्विक छवि में बढ़ा लग जाता। देश समझ जाता कि मोदी के खोखले दावे हैं जो वह और उनकी पार्टी एक मजबूत वैश्विक नेता पर उन्हें पेश कर रहे हैं। पाठकों को याद होगा कि मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद करीब 2 साल तक मोदी विदेश दौरों के द्वारा एक वैश्विक नेता बनने के प्रयोजित प्रचार में लगे थे। यह बात इसलिए भी रेखांकित की जानी चाहिए क्योंकि इसी साल मोदी अपने को पूरी दुनिया के मजबूत नेताओं में शामिल कराने की जुगत में लगे थे और दूसरी तरफ उनके ही लोगों को आईएसआईएस ने मार डाला था।

हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कहा था कि हरजीत मसीह सरासर झूठ बोल रहा है। अब जब खुद सुषमा ने इस खबर की पुष्टि की कि सभी 39 भारतीय मारे जा चुके हैं, उसके बाद मसीह एक बार फ़िर मीडिया के सामने आए हैं।

सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्यों इन्होंने सभी भारतीय मजदूरों के मारे जाने की पुष्टि की तो यहां तक कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सरकार ने अब तक इन मौतों का खुलासा नहीं किया था। वह अपनी राजनीतिक रोटियां संकेती रही और मृतकों के बीच में से लौटे मसीह की बात पर भी यकीन नहीं किया, बल्कि उसे झूठ करार दे दिया।

सुषमा स्वराज ने 26 जुलाई 2017 को लोकसभा में दिए एक बयान में कहा था, 'न हमें लालें मिलते, न हमें खुन के धब्बे मिलते। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो मार दिए गए। हमारा सारा कह रहा है कि वो जिंदा हैं।' तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें मृत मानकर तलाश छोड़ देना चाहिए या उनकी तलाश जारी रखनी चाहिए? मैं उन लोगों से सीधी संपर्क में नहीं हूं। मेरे पास उनके जिंदा होने के सबूत नहीं हैं लेकिन मेरे पास उनके जिंदा होने के सबूत ही नहीं हैं।'

पर अब नाटकीय बयान विदेश मंत्री का ये आया है..

चूंकि अब तक इस बात के प्रमाण नहीं थे कि मारे गए लोग भारतीय ही हैं, इसलिए हमने इस बात की पुष्टि नहीं की थी। मोसुल में दफन भारतीयों के डीएनए के सेंपल रेतीली मिट्टी से लेकर उनके परिजनों के साथ मैच किए गए, जो मैच हो चुके हैं।

गौरतलब है कि इराक में मारे गए इन भारतीयों के शवों की एक सामूहिक कब्र मिली है। इस बात की पुष्टि इराकी प्रशासन ने भी कर दी है। जून 2017 में मोसुल को आईएसआईएस से मुक्त कराया था।

इराक प्रशासन के मुताबिक पिछले साल जो शव एक सामूहिक कब्र में मिले थे, वो उन्हीं भारतीय मजदूरों के थे, जिन्हें 2014 में आईएसआईएस ने मोसुल में बंधक बनाकर मार की नींद सुला दिया गया था। जहां पर 39 लोगों की सामूहिक कब्र बरामद हुई वह उत्तर-पश्चिम में बादेश गांव है जिसे पिछले साल ही इराकी बलों ने अपने कब्जे में लिया है। इराक के शहीद संस्थान के प्रमुख ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि 39 शवों में 38 की पहचान की जा चुकी है।

मोसुल पर कब्जा करने के बाद आईएसआईएस ने भारत के 40 मजदूरों को भी बंधक बना लिया था। इनमें से एक मजदूर हरजीत मसीह अपनी जान बचाने में सफल हुआ था।

आईएसआईएस के चंगुल से बचकर निकले हरजीत मसीह के सुतुकिय, आतंकी हम 40 लोगों को बंधक बनाने के कुछ दिनों बाद बाहर ले गये, जहां पर हमें गोलियों से भूत दिया गया। मैं किसी तरह बांगलादेशी नागरिक की पहचान बताकर वहां से निकलने में कामयाब हो पाया। मृतकों के परिजन चीच—चीचकर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार ने उन्हें क्यों अंधेरे में रखा। बाजाय सरकार के उन्हें अपनों के मरने की खबर मीडिया

सही मिस्री आदि होते। मूर्खों की सरकार वर्कशॉप का खर्च बचा कर खुश है लेकिन कंडम हुई जा रही बसों से होने वाले नुकसान को काइ चिन्ना नहीं। पक्के एवं स्थाई ड्राइवर-कंडेक्टर के बदले में ठेकदारी में कच्चे रख कर बचत करने की तो सरकार सोचती है लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार स्टाफ़ से जो नुकसान होता है